प्रेषक,

सहदेव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांकः 31 अगस्त, 2020**

विषयः- मैसर्स के.आर.एस. हैण्डीक्राफ्ट्स, प्लाट नं-0जी 326-.व 327, फेज2- मसूरी, गुलावटी, यू.पी.एस.आई.डी.सी., इण्डस्ट्रीयल एरिया, हापुड़ स्थित फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को विस्तारीकरण हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 योजनान्तर्गत पूंजीगत अनुदान की धनराशि रू0-50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-5020/2020-21/374, दिनांक-14.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1255/58-2-2017-600(7)/2017टी0सी0, दिनांक-24.11.2017 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की बैठक दिनांकः 01.06.2020 को **मैसर्स के.आर.एस. हैण्डीक्राफ्ट्स, प्लाट नं-0 जी 326-.व 327, फेज2- मसूरी, गुलावटी, यू.पी.एस.आई.डी.सी., इण्डस्ट्रीयल एरिया, हापुड़ स्थित फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को विस्तारीकरण हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान स्वीकृत किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु सब्सिडी मद से शासनादेश संख्या-62/2020/340/58-2-2020-300(1)/2020, दिनांक-26/05/2020 द्वारा माह जून, 2020 हेतु धनराशि रू0-250.00 लाख तथा संख्या-75/2020/563/58-2-2020-300(1)/2020, दिनांकः 05.08.2020 द्वारा माह जुलाई, 2020 हेतु धनराशि रू0-250.00 लाख की व्यवस्था निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेखानुसार **मैसर्स के.आर.एस. हैण्डीक्राफ्ट्स, प्लाट नं-0जी 326-.व 327, फेज2- मसूरी, गुलावटी, यू.पी.एस.आई.डी.सी., इण्डस्ट्रीयल एरिया, हापुड़ स्थित फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट को विस्तारीकरण हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत पूँजीगत निवेश अनुदान **रू0-50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्रावधानों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-21.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-15/2019/205/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-22.02.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

(3) अनुदान हेतु स्वीकृत की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्रयान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

(4) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2021 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(8) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्रयान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक, मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(9) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(10) उक्त पूँजीगत अनुदान की धनराशि संस्था के टर्म लोन के खाते में निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक-24.03.2020 संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक-07.04.2020 एवं संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक-11.04.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सहदेव)
विशेष सचिव।

संख्या-78/2020/618(1)/58-2-2020, तद्दिनांक:

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।
(2) जिलाधिकारी, **हापुड** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) संबंधित संस्था।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in